दैनिक जागरण
जनहित सबसे ऊंचा उद्देश्य है

इमरान का बेसुरा राग

पुलवामा में भीषण आतंकी हमले के कई दिन बाद इस घटना पर कुछ बोलने के लिए आगे आए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सके। इमरान ने हमेशा की तरह आतंकी हमले में पाकिस्तान की लिप्तता के सुबूत मांगकर देश-दुनिया को गुमराह करने की ही कोशिश की। इसी के साथ उन्होंने यह कहकर भारत को धमकाया भी कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा। इस सबके साथ ही उन्होंने बातचीत से समस्या का हल निकालने की पेशकश की और यह रोना भी रोया कि पाकिस्तान तो खुद ही आतंकवाद का शिकार है। इस रुदन में किसी की दिलचस्पी इसलिए नहीं हो सकती, क्योंकि खुद उसके पाले-पोसे आतंकियों ने ही उस पर कहर ढाया है। पेशावर के एक स्कूल में हुआ हमला इसका सबसे बड़ा सुबूत था। आखिर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने यह सोच भी कैसे लिया कि भारत उन पर भरोसा करने के लिए तैयार हो सकता है? इमरान पुलवामा हमले में शामिल जिस आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ सुबूत मांग रहे हैं उसका सरगना तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के साये में ही पल रहा है। क्या इमरान इससे अवगत नहीं कि वह पठानकोट हमले के बाद से ही आइएसआइ के संरक्षण में रह रहा है? यह वही आतंकी सरगना है जिस पर चीन इसलिए संयुक्त राष्ट्र की पाबंदी नहीं लगने दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इमरान खान पर भरोसा इसलिए भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तो वह दिखावटी प्रधानमंत्री हैं और दूसरे, हर कोई इससे अच्छी तरह परिचित हो चुका है कि पाकिस्तान आतंकी हमलों में अपने लोगों के हाथ होने के सुबूत मांगकर किस तरह वक्त जाया करने के साथ ही नए हमलों की साजिश रचता है। भारत यह कभी नहीं भूल सकता कि मुंबई हमले की साजिश रचने वाले आतंकियों के खिलाफ तमाम सुबूत दिए जाने के बाद भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। ये आतंकी न केवल खुले आम घूम रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के शिक्षा संस्थानों में जाकर भारत के खिलाफ आग उगलने में लगे हुए हैं।

मुंबई हमले के गुनहगारों और मसूद अजहर के अलावा पाकिस्तान तमाम सुबूतों के बावजूद एक अन्य आतंकी सरगना दाऊद इब्राहीम को भी कराची में पाल रहा है। ऐसे काम वही कर सकता है जिसने आतंकवाद को अपने शासन की नीतियों का हिस्सा बना लिया हो। पाकिस्तान आतंकवाद का निर्यात भारत के साथ-साथ अफगानिस्तान और ईरान में भी करने में लगा हुआ है और इसी कारण दुनिया उसकी बातों का भरोसा नहीं करती। समस्या यह है कि विश्व समुदाय पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ मानने के बावजूद उसकी अनदेखी करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही उसे आर्थिक मदद देने को तैयार न हों, लेकिन वह अफगानिस्तान को उन तालिबान के हवाले करने को तैयार हैं जिन्हें पाकिस्तान का खुला समर्थन प्राप्त है। ऐसी हालत में भारत को ही यह देखना होगा कि वह पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए क्या कदम उठाए? निःसंदेह केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि भारत ने इमरान के बयान को नकार दिया। इसके साथ ही उसे और भी बहुत कुछ करना होगा।

संयम का वक्त

पिछले दिनों पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर हुए हमले के बाद उत्तराखंड में भी उबाल है। चारों ओर गम और गुस्से के बीच पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस प्रदर्शन और नारेबाजी का दौर थम नहीं रहा है। ऐसे में देहरादून और रुड़की में कश्मीर युवाओं का मामला चिंता बढ़ाने वाला है। दून में पढ़ रहे कुछ कश्मीरी छात्रों ने सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणी वायरल कर दीं, जिससे जन आक्रोश भड़क गया। यही स्थिति रुड़की में भी देखने को मिली। वहां भी एक कश्मीर युवक ने सेना पर टिप्पणी की तो हालात काबू से बाहर होते दिखे, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते स्थिति संभाल ली। दरअसल देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस कश्मीरी छात्रों और लोगों की सुरक्षा के लिए भी चिंतित है। यही वजह है कि एक दिन पहले उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) ने कश्मीरी छात्र-छात्राओं से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट न करें और भरोसा दिलाया कि पुलिस उनकी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। इसके अलावा पुलिस के आला अफसरों ने कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को लेकर मंथन भी किया। देवभूमि स्वभाव से ही सहिष्णु है। जाहिर है यहां रहने वाले बाहरी छात्र-छात्राओं अथवा लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। अतिथि देवो भवः की परंपरा निभाने वाली इस भूमि ने सदा ही अतिथियों का स्वागत किया है और उन्हें सुरक्षा दी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो माहौल बना हुआ है उसमें पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी न केवल बढ़ गई है, बल्कि संवेदनशील होने की भी दरकार है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जिन शिक्षण संस्थाओं में ये छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वे सुरक्षा का ध्यान रखें। साथ ही यह भी जरूरी है कि प्रवेश देने से पहले यह तहकीकात अवश्य की जाए कि किसी का रिकॉर्ड आपराधिक तो नहीं है, क्योंकि कई बार यह भी देखने में आया है कि पढ़ाई की आड़ में कई असमाजिक तत्व भी संस्थानों में प्रवेश ले लेते हैं।

महंगाई के मोर्चे पर बड़ी कामयाबी

डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन

महंगाई का कम होना ही वह पहला, लेकिन महत्वपूर्ण कदम है जिससे आम जनता के साथ-साथ कंपनियों के लिए भी उधारी लागत को घटाना संभव हो पाता है

हाल में लोकसभा से पारित अंतरिम बजट 2019-20 में औसत नागरिकों, विशेषकर मध्यम वर्ग के जीवन को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। चूंकि बजट में घोषित विभिन्न कदम पिछले पांच वर्षों में किए गए अनगिनत उपायों की परिणति के प्रमाण हैं इसलिए हमें यह बात भली-भांति समझनी चाहिए कि इस दौरान मध्यम वर्ग के आम लोगों का जीवन किस तरह से अत्यंत आसान हो गया है। विशेषकर महंगाई में आई उल्लेखनीय कमी और वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की बदौलत प्रभावी कर दरें घट जाने से बचत बढ़ने और उपभोग पर खर्च घटने से लोगों की क्रय क्षमता में खासा इजाफा हुआ है। महंगाई आम लोगों के लिए बहुत दुखदायी होती है। यह एक तरह का कष्टदायक कर होती है। जो महंगाई दर वर्ष 2013-14 में 10.1 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी वह दिसंबर 2018 में काफी घटकर सिर्फ 2.2 प्रतिशत के स्तर पर आ गई। महंगाई के वास्तविक असर को समझने के लिए हमें यह बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि महंगाई आम जनता की गाढ़ी कमाई से खाद्य पदार्थों, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदने की उनकी क्षमता को बुरी तरह प्रभावित करती है। यदि एक किलोग्राम चावल की कीमत वर्ष 2014 में 50 रुपये थी और यदि महंगाई दर पिछले पांच वर्षों के दौरान निरंतर दहाई अंकों में बरकरार रहती तो ठीक उतने ही यानी एक किलोग्राम चावल की कीमत आज 80 रुपये बैठेगी। अब इसकी दूसरी तस्वीर पर गौर कीजिए। यदि पांच वर्षों की इस अवधि के दौरान महंगाई दर के औसतन 4.5 प्रतिशत रहने से ठीक उतने ही यानी एक किलोग्राम चावल की कीमत आज 62.5 रुपये है। अतः प्रति माह 5,000 रुपये खर्च करने वाला परिवार आज 80 किलोग्राम चावल खरीद सकता है, जबकि महंगाई दर के वर्ष 2014 के स्तर पर ही बरकरार रहने की स्थिति में यह परिवार केवल 62.5 किलोग्राम चावल ही खरीद पाता। इसका मतलब यही हुआ कि महंगाई दर के नरम रहने से परिवार की क्रय क्षमता लगभग 28 प्रतिशत बढ़ गई है। कुल मिलाकर किसी भी औसत परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के मामले में यह बढ़ी हुई क्रय या खरीद क्षमता से संबंधित परिवार की खुशहाली में आशातीत वृद्धि हुई है, क्योंकि उसके बजट में एक बड़ा हिस्सा इन वस्तुओं का ही होता है।

दूसरी अहम बात यह है कि महंगाई का असर बचत की वास्तविक दरों पर भी पड़ता है। जब महंगाई दर वर्ष 2014 तक दहाई अंकों में थी तब कोई भी बचतकर्ता प्रति वर्ष (-)2 प्रतिशत ब्याज अर्जित करता था। दूसरे शब्दों में, किसी सावधि जमा में अपनी गाढ़ी कमाई निवेश कर एक औसत नागरिक अपनी क्रय क्षमता को बढ़ाने के बजाय कम करता जा रहा था। इसके विपरीत, पिछले चार वर्षों में महंगाई की औसत दर लगभग 4 प्रतिशत रहने के परिणामस्वरूप बचत की वास्तविक दरें तकरीबन 3 प्रतिशत आंकी गईं जो सही मायनों में पांच प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं। अतः यदि महंगाई दर वर्ष 2014 के स्तर पर ही बरकरार रहती तो बचतकर्ताओं की क्रय क्षमता वर्तमान स्तर के मुकाबले लगभग 25 प्रतिशत कम होती। चूंकि वरिष्ठ नागरिक अपनी सेवानिवृत्ति राशि को विशेषकर सावधि जमाओं में लगाकर उस पर अर्जित होने वाले ब्याज पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए बचत राशि की क्रय क्षमता बढ़ने से ये पेंशनभोगी ही सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं।

अवधेश राजपूत

एक महत्वपूर्ण ढांचागत बदलाव यथा मौद्रिक नीति की रूपरेखा के कार्यान्वयन की बदौलत ही कम महंगाई संभव हो पाई है। दरअसल, मौद्रिक नीति की रूपरेखा के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई दर को 2 से 6 प्रतिशत के बीच लक्षित किया। महंगाई को कम करने में मिली सफलता विशेष मायने रखती है, क्योंकि महंगाई का कम होना ही वह पहला, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है जिससे आम जनता के साथ-साथ कंपनियों के लिए भी उधारी लागत को घटाना संभव हो पाता है। देश का मध्यम वर्ग कम महंगाई के लाभ के असर को पहले ही महसूस कर चुका है, जो होम एवं कार लोन पर देय ब्याज के साथ-साथ क्रेडिट कार्ड की भुगतान राशि में कमी के रूप में प्राप्त हुआ है। आर्थिक विकास की तेज रफ्तार हासिल करने वाले प्रत्येक देश ने इस मोर्चे पर कामयाबी पाई है, क्योंकि उधारी लागत घटने से अर्थव्यवस्था की विभिन्न गतिविधियों में निवेश को काफी बढ़ावा मिलता है। मध्यम वर्ग द्वारा अदा किए जाने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की प्रभावी दरों में कमी के साथ-साथ कर रिटर्न दाखिल करना और रिफंड प्राप्त करना आसान हो जाने से भी मध्यम वर्ग काफी लाभान्वित हुआ है।

अब हम वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के असर पर विचार करते हैं। जीएसटी लागू होने से पहले और उसके बाद के पारिवारिक खर्च का विश्लेषण करने से यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि लगभग 100 वस्तुओं पर टैक्स की दरें घट गई हैं जिनमें खाद्य एवं पेय पदार्थ, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन, वाशिंग पाउडर, जूते-चप्पल इत्यादि शामिल हैं। यदि हम हर महीने इन वस्तुओं पर 8,400 रुपये खर्च करने वाले परिवार पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि जीएसटी के तहत उसके द्वारा अदा की गई टैक्स राशि 320 रुपये कम हो गई है, क्योंकि दोहरा कर अब समाप्त हो गया है। उपभोक्ता आम तौर पर किसी भी उत्पाद की पैकेजिंग पर छपी जीएसटी दर पर ही अपनी नजर डालते हैं और वे यह मान लेते हैं कि टैक्स की प्रभावी दर बढ़ गई है। हालांकि, जीएसटी का भुगतान केवल मूल्य वर्धन (वैल्यू एडिशन) या बढ़े हुए मूल्य पर ही किया जाता है। अतः उपभोक्ताओं को केवल जीएसटी दर के बजाय जीएसटी के तहत अदा की गई वास्तविक राशि को ही ध्यान में रखना चाहिए।

टैक्स की प्रभावी दर में कमी करने के साथ-साथ टैक्स रिटर्न दाखिल करना भी काफी आसान कर दिया गया है, ताकि मध्यम वर्ग के ज्यादातर लोग अपने-अपने टैक्स रिटर्न ऑनलाइन दाखिल कर सकें और जल्द ही रिफंड प्राप्त कर सकें। सरकारी कोशिशों से 99.54 प्रतिशत रिटर्न के लिए किसी भी टैक्स अधिकारी या कर्मचारी से संपर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी है। वहीं, दूसरी ओर जिन 0.46 प्रतिशत रिटर्न के लिए किसी टैक्स अधिकारी या कर्मचारी से संपर्क करने की जरूरत पड़ी है, उनमें मध्यम वर्ग के ईमानदार करदाताओं के शामिल होने की संभावना नहीं है। आम जनता के लिए कर अनुपालन अत्यंत आसान हो गया है। दरअसल, इन परिवर्तनों की बदौलत सरलीकरण का वह अगला चरण शुरू करने का भी समय अब आ गया है, जिसमें 24 घंटे के अंदर ही टैक्स रिटर्न का आकलन हो जाएगा और इसके साथ ही रिफंड की प्रोसेसिंग भी पूरी हो जाएगी। बजट भाषण में भी इसका उल्लेख किया गया है। कुल मिलाकर, मध्यम वर्ग के लिए बजट में घोषित किए गए अनगिनत लाभ विगत पांच वर्षों के दौरान निर्मित महत्वपूर्ण संरचना की विशेष अहमियत को दर्शाते हैं।

(लेखक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं)

response@jagran.com

राजनीतिक नेतृत्व की नाकामी के तीन दशक

राजीव सचान

1989 में कश्मीर के अशांत होने के बाद से ही हम पाकिस्तान के हाथों आहत-अपमानित होते चले आ रहे हैं

पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुआ हमला राष्ट्र की चेतना और साथ ही उसके स्वाभिमान पर करारा आघात था, लेकिन उसका सामना करने में हम एक राष्ट्र के रूप में वैसी परिपक्वता, एकजुटता और दृढ़ता नहीं प्रदर्शित कर सके जैसी अपेक्षित ही नहीं अनिवार्य थी। देश के मर्म पर चोट करने वाले इस हमले की खबर मिलते ही स्वाभाविक तौर पर उसकी निंदा और भर्त्सना शुरू हो गई। इसे कायराना हमला कहा गया, लेकिन यह तो घिनौने दुस्साहस की पराकाष्ठा थी। जब सर्वदलीय बैठक बुलाने की घोषणा हुई तो ऐसा लगा कि सभी राजनीतिक दल अपने दलगत हित और स्वार्थों का परित्याग कर समवेत स्वर में ऐसा कुछ कहेंगे जिससे दुनिया को भारत की एकजुटता और दृढ़ता का संदेश जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस सर्वदलीय बैठक में जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ वह इतना पिलपिला था कि उसने कहीं कोई प्रभाव नहीं छोड़ा। आश्चर्य केवल यह नहीं कि इसमें पाकिस्तान का दूर-दूर तक नाम न था। यह भी था कि इसकी भाषा में कोई तेज-ओज न था। घिसी-पिटी सरकारी भाषा वाला यह एक नीरस और निष्प्राण प्रस्ताव था। इस भाषा में भी संशोधन करना पड़ा, क्योंकि कुछ दलों को किसी वाक्य पर आपत्ति थी। देश जानना चाहेगा कि वह क्या था जिस पर कुछ दलों को आपत्ति थी और जिसके चलते प्रस्ताव की भाषा बदली गई?

अगर हमारा राजनीतिक नेतृत्व गहन संकट के समय कोई ढंग का राजनीतिक प्रस्ताव भी तैयार नहीं कर सकता तो उससे कोई उम्मीद कैसे की जा सकती है? इस प्रभावहीन प्रस्ताव की जड़ में वह राजनीतिक क्षुद्रता और स्वार्थपरता ही झलकी जिसने पिछले दो-तीन दशकों में अपनी जड़ें और गहरी कर ली हैं। जब देश शोकमग्न था तब राजनीतिक दलों को कैसे अपने राजनीतिक हितों की चिंता सता रही थी, यह उनकी रैलियों और सभाओं से प्रकट हुआ। इनके जरिये आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला कायम हो गया। क्या पक्ष-विपक्ष के राजनीतिक दल कुछ दिन ठहर नहीं सकते थे? जब यह अपेक्षित था कि सभी दल एक स्वर में बोलते तब वे अलग-अलग स्वर में बोलने लगे और इस तरह शोक के वातावरण में राजनीतिक नकारात्मकता घुलने लगी। इसकी एक बानगी तब मिली जब वंदे भारत एक्सप्रेस में क्षणिक खराबी आने पर उसका उपहास उड़ाया जाने लगा। एक क्षण को ऐसा लगा कि यह देश की नहीं, भाजपा की निजी ट्रेन थी, जो उसकी खराबी पर विरोधी दल खुद को आनंदित होने से नहीं रोक पा रहे थे। इस प्रसंग ने एक बार फिर यही बताया कि सरकार विरोध और देश विरोध के बीच का अंतर किस तरह धुंधला हो गया है। क्या विरोधी दल के लोग या फिर सरकार के कटु आलोचक इस पर भी खुश होना पसंद करेंगे कि सूर्यकिरण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए?

आम तौर पर दुनिया में हर आतंकी हमला सुरक्षा में चूक का नतीजा होता है। पुलवामा हमले में भी सुरक्षा-सतर्कता में कमी साफ दिख रही है। इस कमी का उल्लेख किया ही जाना चाहिए, लेकिन आखिर ऐसे वाहियात सवाल का क्या मतलब कि यह हमला चुनाव के ठीक पहले क्यों हुआ? यह सवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है जो प्रधानमंत्री बनना चाह रही हैं। इस चाहत में कोई बुराई नहीं, लेकिन उनके इस सवाल का जवाब तो जैश ए मोहम्मद या फिर पाकिस्तानी सेना ही दे सकती है कि पुलवामा में हमला इसी समय क्यों किया गया?

राजनीतिक दलों के चिंतन और विमर्श में गिरावट रातोंरात नहीं आई। यह एक अर्से से जारी है और इसमें सभी दलों का बराबर योगदान है-कांग्रेस, भाजपा से लेकर कमल हासन की ओर से नए बनाए गए राजनीतिक दल का भी। कमल हासन को लगता है कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। कमल हासन इसके उदाहरण हैं कि हमने कैसे कुछ सतही सोच वाले कलाकारों को फिल्मी पर्दे पर उनके अभिनय के आधार अपना नायक मान लिया है। साफ है कि कमल हासन को इसका ज्ञान भी नहीं कि कश्मीर में जनमत संग्रह संबंधी संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव क्या कहता है।

पुलवामा में हमले के बाद सबसे गंभीर बात यह है कि देश की न तो कोई कश्मीर नीति दिख रही है और न ही पाकिस्तान संबंधी नीति। ऐसी कोई नीति शायद इसीलिए नहीं बन सकी, क्योंकि सरकारें आती-जाती गईं और वे अपने हिसाब से कश्मीर और पाकिस्तान संबंधी नीति में अपने मन मुताबिक फेरबदल करती गईं। नतीजा यह हुआ कि कहीं कोई स्पष्ट नीति रह ही नहीं गई। यह स्थिति इसलिए भी बनी, क्योंकि राजनीतिक दलों के लिए देश के दीर्घकालिक हित पहली प्राथमिकता नहीं बन सके। एक समय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि दल बनेंगे-बिगड़ेंगे, सरकारें आएंगी-जाएंगी, लेकिन यह देश रहना चाहिए। लगता था कि हमारे राजनीतिक दल इसी भावना से काम करते होंगे, लेकिन अब इसमें संदेह होने लगा है।

कायदे से कश्मीर को शांत करने और पाकिस्तान में पनप रहे खतरे का सामना करने की कोई ठोस नीति तभी बन जानी चाहिए थी जब 1989 में उसने वहां दखल देना शुरू किया था। ऐसा नहीं किया गया। इसके दस साल बाद 1999 में कश्मीर के कारण ही कारगिल में घुसपैठ हुई और वह एक सैन्य संघर्ष में तब्दील हो गई। सैकड़ों सैनिकों ने बलिदान दिया, लेकिन शायद जरूरी सबक नहीं सीखे गए। इसके करीब दस साल बाद 2008 में मुंबई में सबसे भीषण आतंकी हमला हुआ। तमाम गर्जन-तर्जन के बाद भी पाकिस्तान को सबक सिखाने की किसी नीति पर अमल होते हुए नहीं दिखा। इसके बाद रह-रह कर आतंकी हमले होते रहे और हम रह-रह कर इस उम्मीद में पाकिस्तान के साथ वार्ता की मेज पर जाकर बैठते रहे कि शायद अबकी बार वह सही रास्ते पर आ जाए। मुंबई हमले के करीब दस साल बाद पुलवामा में भीषण हमला शायद इसीलिए हुआ, क्योंकि न तो कश्मीर को शांत करने की कोई व्यापक पहल हुई और न ही पाकिस्तान पर लगाम लगाने की।

एक तरह से देखा जाए तो तीस साल बीत गए हैं और हम पाकिस्तान के हाथों आहत-अपमानित होते चले आ रहे हैं। हमारी एक के बाद एक सरकारों ने दुनिया से यह अपेक्षा व्यक्त की कि वह पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करे, लेकिन हम खुद वह काम नहीं कर सके जो औरों से चाहते थे। निःसंदेह इसका यह मतलब नहीं कि पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने मात्र से वह काबू में आ जाता, लेकिन आखिर कुछ तो ठोस किया जाना चाहिए था। दूसरी ओर यह साफ दिखता है कि भारत को लहूलुहान करने की अपनी नीति पर पाकिस्तान न केवल कायम है, बल्कि वह उसे और धार भी दे रहा है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सफलता

कामयाबी के शिखर पर कुशलता के सोपानों से चढ़ा जाता है। सफलता बौद्धिक प्रतिभा का संग्रह मात्र नहीं, बल्कि बौद्धिक क्षमता के समुचित सुनियोजन की कुशलता का नाम है। सफलता एक ऐसी तकनीक है, जो अर्जित ज्ञान को समय की मांग के अनुरूप क्रियाशील एवं क्रियान्वित कर सके। नई सोच, नए विचार एवं नित नई कुशलता सफलता के सूत्र हैं। ये सूत्र भौतिक जीवन से लेकर आध्यात्मिक जीवन में भी प्रयुक्त होते हैं। भौतिक जीवन के नूतन आविष्कार और उनकी व्यावहारिक उपयोगिता इसी का परिणाम है। सफलता के लिए समय एवं परिस्थिति के अनुरूप ढलने की आवश्यकता होती है।

पूर्वाग्रही, दुराग्रही एवं हठाग्रही व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए, क्योंकि वे अपनी आदतों, मान्यताओं, आग्रहों और दुराग्रहों की सीमा में इस कदर कैद होते हैं कि वह इससे परे कुछ सोच ही नहीं सकते। ऐसी मानसिकता बदली हुई परिस्थितियों की आहट को सुनने-समझने में पूर्णतः अक्षम-असमर्थ होती है। किसी क्षेत्र में सफलता के लिए उस क्षेत्र के सारे आयामों से संबंधित सूचनाओं के संग्रह की जरूरत होती है। इसके अलावा किसी वांछित विषय के स्वरूप को मनोयोगपूर्वक सही ढंग से समझना और उसे क्रियान्वित करने की तकनीक खोजना महत्वपूर्ण है। सफल होने के लिए उपलब्ध एवं अर्जित ज्ञान को नवीनतम तथ्यों और तकनीकों से समन्वित करके प्रस्तुत करना सफलता का मार्ग है।

कुशल कलाकार अपने कलात्मक कौशल से अपनी कला को सफलता के शिखर तक पहुंचा देता है। हमारे पास जो है या हम जिसे प्राप्त करने जा रहे हैं, उसे वर्तमान में कैसे उपयोगी एवं व्यावहारिक बनाया जा सकता है? इस बात की खोज ही सफलता का आधार है। इसलिए सफल होने के लिए ज्ञानार्जन के अलावा इस बारे में तकनीकी ज्ञान प्राप्त करते हुए इस ज्ञान के प्रयोग की कुशलता का अभ्यास परम आवश्यक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता के लिए धैर्य की भी बहुत आवश्यकता है। जैसे पौधा एक दिन में वृक्ष नहीं बन जाता, ठीक उसी प्रकार सफलता का भी कोई 'शॉर्टकट' नहीं होता। जब हम एक नियत समय तक प्रयास करेंगे तो कालांतर में उसका परिणाम मिलेगा।

डॉ. सुरचना त्रिवेदी

आभा खोती अरावली

देवेंद्रराज सुथार

अवैध खनन ने न केवल अरावली के स्वरूप को बदल दिया है, बल्कि प्राकृतिक जल तंत्र को भी दूषित कर दिया है

राजस्थान में अरावली का 80 प्रतिशत भाग मौजूद है, लेकिन पिछले कुछ सालों से खनन माफियाओं की मनमानी के कारण इसकी आभा खोती जा रही है। खनन माफिया खुलेआम अरावली पहाड़ियों में जमकर अवैध खनन कर रहे हैं। पुलिस-प्रशासन को भी इसकी कोई परवाह नहीं है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान से अरावली की 31 पहाड़ियां गायब होने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए राजस्थान सरकार से पूछा था कि क्या अरावली की पहाड़ियों को लोग हनुमान बनाकर उठा ले गए? शीर्ष अदालत ने 48 घंटे के भीतर अवैध खनन को बंद करने के आदेश दे दिए थे, लेकिन तमाम आदेशों के बावजूद भी प्रदेश में चोरी-छिपे अवैध तरीके से अरावली पर खनन कार्य होना राज्य सरकार के अवैध खनन को रोकने के प्रयासों पर सवालिया निशान लगा रहा है। हालांकि वन विभाग के नियमों के अनुसार अगर एक बार कोई वाहन या व्यक्ति अवैध खनन में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाता है। अगर तीन बार कोई वाहन अवैध खनन का परिवहन करते पाया जाता है तो उस वाहन को सीज कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी खनन माफियाओं में कोई डर नहीं है।

गौरतलब है कि प्री-क्रैम्बियन काल में बनीं अरावली की पहाड़ियां एक वलित पर्वत शृंखला हैं। अरावली शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों 'अरा' और 'वली' से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है 'चोटियों की रेखा', लेकिन कुछ रेफरेंस कहते हैं कि अरावली दरअसल आडावली का अपभ्रंश है। और आडावली इसलिए, क्योंकि यात्रा करते वक्त ये पहाड़ियां यात्रियों के आड़े आती थीं। यह पर्वतमाला देश के उत्तरी-पश्चिमी भाग में फैली हुई है। अर्थात ये पहाड़ियां भारत के चार राज्यों राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में 692 किलोमीटर में फैली हुई हैं। इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। दक्षिणी भाग में ये अधिक चौड़ी और ऊंची हैं, जबकि उत्तर की तरफ जाते हुए इनकी ऊंचाई कम होते जाती है। इसकी दक्षिणी पहाड़ियों में ही हरियाली और घने जंगल पाए जाते हैं, जबकि उत्तर के ज्यादातर क्षेत्र रेतीले और पथरीले हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु-शिखर है जो सागर तल से 1,722 मीटर ऊंची है। यह माउंट आबू शहर में स्थित है।

अगर अरावली की ये पहाड़ियां नहीं बचीं तो इनके माध्यम से मिलने वाले ढेरों खनिजों-सीसा, तांबा, जस्ता आदि के लाभ से हमें वंचित होना पड़ेगा। इससे निकलने वाली बाना, लूनी, साखी, साबरमती, केन, बेतवा, धसान, सिंध, पार्वती, काली सिंधु, बनास जैसी नदियां देखने को नहीं मिलेंगी। यही नहीं इन पहाड़ियों के पश्चिम में विशाल थार मरुस्थल स्थित है। पहाड़ियां इसे पूर्व की ओर फैलने से रोकती हैं। कई ऐसी प्रजातियां जो अन्यथा नहीं पाई जातीं या लुप्त होने के कगार पर हैं, यहां मिल जाएंगी। भील जैसी कितनी ही आदिवासी प्रजातियों का रहवास भी इनमें है। इसकी ही बदौलत माउंट आबू, आबू का विशाल नखी तालाब और उदयपुर जैसे पर्यटक स्थल आय के स्रोत बने हुए हैं। अरावली के उजड़ने का सीधा मतलब इन सबको खोना है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

कब सुधरेंगे कश्मीर के हालात

बलबीर पुंज ने अपने आलेख 'विषाक्त मानसिकता से बिगड़े हालात' के माध्यम से कश्मीर घाटी में व्याप्त आतंकवाद रूपी अराजकता पर दुख व्यक्त किया है। कश्मीर घाटी प्रकृति द्वारा रची गई अद्भुत कला का उदाहरण है। यह प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, परंतु यह दुखद है कि वहां आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं, जिसके कारण वहां के स्थानीय निवासी दहशत में जीवन यापन कर रहे हैं। आतंकवाद के कारण वहां आने वाले पर्यटक भी असुरक्षित महसूस करते हैं। कश्मीर घाटी में व्याप्त आतंकवाद रूपी अराजकता का जिम्मेदार कौन है? आखिर कैसे आतंकी हमारे देश में घुस जाते हैं और देश को क्षति पहुंचाते हैं? यह समझना जरूरी है कि आतंक से किसी का भला नहीं होता, अपितु इससे केवल अशांति का माहौल पनपता है। आतंकवाद कैंसर सरीखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कैंसर मानव शरीर को क्षति पहुंचाता है, परंतु आतंकवाद देश के साथ-साथ संपूर्ण मानवता को नष्ट कर देता है। आतंक मचाने वाले अपनी कमजोर मानसिकता को प्रमाणित करते हैं। इस दुनिया को रचने वाले ने हम सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है। हमें बुद्धि दी है ताकि हम मानवता की रक्षा कर सकें। आज मानवता खतरे में है। इसकी रक्षा करना हम इंसानों के हाथों में ही है, जिसके लिए आतंक रूपी अराजकता को त्यागकर प्रेम रूपी वस्त्र को धारण करके मनुष्य होने का प्रमाण देना होगा।

सौरभ पाठक, ग्रेटर नोएडा

देश का माहौल बिगाड़ रहे अराजक तत्व

संपूर्ण देश जहां वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है वहीं देश के अंदर कुछ अराजक तत्व ऐसे भी हैं जो देश के माहौल को बिगाड़ने में लगे हैं। समाज विरोधी तत्व इस बात से नाखुश हैं कि देश में इतनी एकजुटता कैसे है, यही बात उनको हजम नहीं हो रही है और यही कारण है कि ये लोग अवसर देख पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसा कर इन शरारती तत्वों को क्या फायदा मिलता है, यह तो समझ से परे है, लेकिन इतना तो तय है कि राष्ट्रविरोधी लोगों के खिलाफ एकजुट भारत देख उनकी हवाइयां उड़ी है। यह बहुत ही दुखद है कि देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के प्रति ऐसे लोग श्रद्धांजलि देने के बजाय ऐसी करामात कर रहे हैं, जिससे शहीदों के परिवारों को ठेस पहुंच रही है। जवान अपने प्राणों की आहुति देकर हमारी रक्षा कर रहे हैं और कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। यह बहुत ही दुःखद है। इस पर देश के सभी नागरिकों को गंभीरता से सोचना चाहिए।

pathaknirajkumar2013@gmail.com

धारा 370 हटे और शहीद आयोग बने

देश की आत्मा पर आए दिन हो रहे ऐसे हमलों के पीछे कश्मीर में लागू 370 धारा भी है। इसकी वजह से घाटी में आतंकवादियों के हितैषियों को भी खास दर्जा मिलता है। धारा 370 की वजह से वहां पर जांच और ऑडिट जैसे कार्य नहीं हो पाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हमारे वीर जवानों के लिए लेने की आवश्यकता है। अपने देश पर खुद को न्योछावर कर देने वाले ये जवान देश की सरहद पर आते वक्त अपने पीछे अपना भरा पूरा परिवार छोड़ आते हैं। उनके जाने के बाद उनके परिवार को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में समय की यही मांग है कि सरकार एक शहीद आयोग भी बनाए, जो ताउम्र उन परिवार के साथ खड़ा रहे या उनकी जरूरतों का ध्यान रख सके।

rishibhardwaj86@gmail.com

विरोध की अति में हो रही क्षति

पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश में आक्रोश व्याप्त है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने दुश्मन को नीचा दिखाते-दिखाते अपने देश को ही नुकसान